भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2635**
गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 /1 पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

यात्री विमानों का विनिर्माण

2635. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में यात्री विमानों के विनिर्माण के लिए वैश्विक विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए भारत को उपयुक्त गंतव्य बनाने के संबंध में कोई रूप रेखा है;

(ख) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में यात्री विमानों के विनिर्माण के लिए रक्षा गलियारे की तर्ज पर विशेष आर्थिक जोन अथवा विमानन गलियारा बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है:

(घ) क्या सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत कम लागत वाले विमानों के विनिर्माण हेतु घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में कोई नीति या योजना बनाई है। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क): मौजूदा नीति विमानों के घरेलू विनिर्माण को सक्षम बनाती है। सरकार, भारत में सार्वजनिक और निजी उद्यमों के माध्यम से, क्षेत्रीय परिवहन विमान और संबंधित उपकरणों सहित, विमानों के विनिर्माण को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए सुविधा प्रदान कर रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित हिंदुस्तान -228 (उन्नत) नागरिक विमान, 19 सीटर टर्बो प्रॉप कम्यूटर विमान है, जो क्षेत्रीय सम्पर्क के लिए उपयुक्त है। एचएएल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) - राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाएं (एनएएल) के साथ 19 सीट वाले हल्के परिवहन विमान – सरस एमके-II के डिजाइन, विकास एवं प्रमाणन और तत्पश्चात उसके उत्पादन, विपणन और लाइफस्टाइल अनुरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है।

(ख) और (ग): मंत्रालय को, पश्चिम बंगाल में यात्री विमानों के विनिर्माण के लिए, रक्षा गलियारे की तर्ज पर विशेष आर्थिक क्षेत्र या विमानन कॉरिडोर बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य, विभिन्न विमानन उप-क्षेत्रों अर्थात एयरलाइनों, हवाईअड्डों, कार्गो, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं, सामान्य विमानन, एयरोस्पेस विनिर्माण, कौशल विकास आदि के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

******